



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18—अगस्त 24, 2018 (श्रावण 27, 1940)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18—AUGUST 24, 2018 (SHRAVANA 27, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	549	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	591	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	13	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1783	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 6685
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 1927
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1737
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	549	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	591	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	13	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1783	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6685
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1927
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1737
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

सं. 86-प्रेज/2018.—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में दिनांक 25 मार्च, 2017 को प्रकाशित इस सचिवालय के असाधारण कोटि के साहस के लिए 'सेना मेडल' पुरस्कार से संबंधित दिनांक 26 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 33-प्रेज/2017 के हिन्दी रूपांतरण में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

क्रम संख्या 23 में

आईसी-76280एम मेजर मुनेश गुजर, तीसरी बटालियन, दि राष्ट्रीय राइफल्स – के स्थान पर

आईसी-76280एम मेजर मुनेश गुजर, तीसरी बटालियन, दि राजपूत रेजिमेंट— पढ़ा जाए।

क्रम संख्या 41 में

4274698वाई हवलदार श्रीनाथ मुर्मू, 47वीं बटालियन, दि राष्ट्रीय राइफल्स – के स्थान पर

4274698वाई हवलदार श्रीनाथ मुर्मू, दि बिहार रेजिमेंट/47वीं बटालियन, दि राष्ट्रीय राइफल्स – पढ़ा जाए।

क्रम संख्या 51 में

2611130एम नायक नटराजन एन., 7वीं बटालियन, दि मद्रास रेजिमेंट— के स्थान पर

2611130एम लांस नायक नटराजन एन., 7वीं बटालियन, दि मद्रास रेजिमेंट – पढ़ा जाए।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 87-प्रेज/2018.—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में दिनांक 25 मार्च, 2017 को प्रकाशित इस सचिवालय के असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए 'सेना मेडल' पुरस्कार से संबंधित दिनांक 26 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 37-प्रेज/2017 के हिन्दी रूपांतरण में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

क्रम संख्या 3 में

आईसी-39690ए मेजर जनरल हरीश ठुकराल, इन्फैन्ट्री – के स्थान पर

आईसी-39590ए मेजर जनरल हरीश ठुकराल, इन्फैन्ट्री – पढ़ा जाए।

क्रम संख्या 22 में

आईसी-59491के कर्नल लविन्दर सिंह, दि बिहार रेजिमेंट/आरट्रेक मुख्यालय – के स्थान पर

आईसी-51491के कर्नल लविन्दर सिंह, दि बिहार रेजिमेंट – पढ़ा जाए।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ

विशेष कार्य अधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(आईसीआर प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं.एफ.9/1/2018-यू.3 (ए).— जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को समवत विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), एनएआईआर कैम्पस, लालबाग, वडोदरा, गुजरात को समवत विश्वविद्यालय (डी-नोवो श्रेणी के तहत स्थापित किया जाना) का दर्जा प्रदान करने के लिए दिनांक 17.01.2018 को आवेदन प्राप्त हुआ था।

3. और जबकि, आवेदन यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं), विनियम, 2016 के अनुसार परामर्श के लिए यूजीसी को अग्रेषित किया गया था।

4. और जबकि, यूजीसी ने यह सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की थी कि क्या राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), वडोदरा, गुजरात के आवेदन पर डी-नोवो श्रेणी के तहत विचार किया जा सकता है। समिति की, संस्थान के प्रतिनिधि के साथ विस्तृत बातचीत और विचार विमर्श के बाद यह राय थी कि प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम डी-नोवो की परिभाषा के तहत कवर होते हैं जैसाकि यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं), विनियम, 2016 में परिकल्पना की गई है और यह सही मायने में ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में है। समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

“मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान की स्थापना के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ डी नोवो श्रेणी के तहत संस्थान को आशय पत्र जारी किया जाए:

- i प्रस्तावित समवत विश्वविद्यालय के नाम पर अलग और विशेष समिति/ट्रस्ट/कंपनी स्थापित की जाएगी।
- ii सभी परिसंपत्तियां कानूनी रूप से प्रस्तावित समवत विश्वविद्यालय के नाम होंगी।
- iii यूजीसी विनियम, 2016 के अनुसरण में एमओए/नियम तैयार किए जाएं।
- iv यूजीसी विनियम, 2016 के अनुसरण में भूमि, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, आवास और अन्य अवसंरचना बनाई जाएं।
- v ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों की विस्तृत पाठ्यचर्या सहित उभरते हुए क्षेत्र में प्रस्तावित अवरस्नातक और न्यूनतम पांच वर्षीय स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम।
- vi यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हताओं सहित प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए संकाय भर्ती की जाएं।
- vii अन्य प्राधिकारी जैसे कुलसचिव, रजिस्ट्रार, आदि नियुक्त किए जाएं।

इसके अतिरिक्त समिति ने सिफारिश की है कि यूजीसी की विशेषज्ञ समिति भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी (एनएआईआर), वडोदरा, (गुजरात) संस्थान में उपलब्ध अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का स्थल दौरा करे और यह सिफारिश करे कि क्या प्रारंभ किए जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए यूजीसी (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध हैं, यह समिति, वर्तमान समिति से एक सदस्य को शामिल कर सकती है।”

5. और जबकि, यूजीसी (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 के तहत यथाअपेक्षित, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ साथ यूजीसी की अन्य विशेषज्ञ समिति ने संस्थान में उपलब्ध अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के वास्तविक सत्यापन के लिए 18-19 अप्रैल 2018 के दौरान संस्थान का दौरा किया। आयोग ने दिनांक 11.05.2018 को आयोजित अपनी 531 वीं बैठक (मद सं. 2.01) में यूजीसी और एआईसीटीई दोनों की विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पास किया गया:

“राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), एनएआईआर परिसर, लालबाग, वडोदरा, 390004 गुजरात को डी-नोवो वर्ग के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी सुझाव दिया गया था कि एनआरटीआई विद्यार्थियों की प्लेसमेंट के लिए उचित कदम उठाए।”

6. और जबकि, यूजीसी और एआईसीटीई की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और यूजीसी की सलाह पर, मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), वडोदरा, गुजरात को समविश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ 25.05.2018 को रेल मंत्रालय को आशय पत्र जारी किया:-

- i प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय के नाम पर अलग और विशेष समिति/ट्रस्ट/कंपनी स्थापित की जाएगी।
- ii सभी परिसंपत्तियां कानूनी रूप से प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय के नाम पंजीकृत होंगी।
- iii यूजीसी विनियम, 2016 के अनुसरण में एमओए/नियम तैयार किए जाएं।
- iv ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों की विस्तृत पाठ्यचर्या सहित उभरते हुए क्षेत्र में प्रस्तावित अवरस्नातक और न्यूनतम पांच वर्षीय स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम।

- v यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हताओं सहित प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए संकाय भर्ती किए जाएं।
- vi अन्य प्राधिकारी जैसे कुलसचिव, रजिस्ट्रार, आदि नियुक्त किए जाएं।

7. और जबकि, रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों के संबंध में दिनांक 14 जून 2018 को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेज दी थी। इस अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करने एवं इस पर अपनी टिप्पणियां इस मंत्रालय को भेजने के लिए यूजीसी को अग्रेषित किया गया था। इसके जवाब में, यूजीसी ने दिनांक 29 जून, 2018 को अपनी टिप्पणियां इस मंत्रालय को भेज दी थीं।

8. अब, इसलिए, केंद्र सरकार यूजीसी के परामर्श और रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुपालन रिपोर्ट पर दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), एनएआईआर परिसर, लाल बाग, वडोदरा, गुजरात को इस शर्त के अध्यधीन कि एनआरटीयू प्रतिष्ठान (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत रेल मंत्रालय, भारत सरकार की एक गैर लाभकारी कंपनी) एनआरटीआई में शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने से पूर्व अपेक्षित संख्या में संकाय और अन्य प्राधिकारी जैसे कुलपति, रजिस्ट्रार इत्यादि की यूजीसी के मानदंडों के अनुसार नियुक्ति करेगा, डी-नेवो श्रेणी के अंतर्गत पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए एक मानद समविश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। पांच वर्षों के पश्चात् यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा आयोग सिफारिशों के आधार पर लागू विनियमों के प्रावधानों के आधार पर समवत विश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

9. उपरोक्त पैरा 8 में की गई उद्घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम सं. 4 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन है।

ईशिता राय

संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 31st July, 2018

No. 86-Pres/2018.—The following amendments are made in the Hindi version of this Secretariat Notification No. 33-Pres/2017, dated 26th January, 2017 published in Part I Section 1 of the Gazette of India on the 25th March, 2017 relating to the award of 'Sena Medal' for the acts of exceptional courage:-

At. S. No. 23

For – IC-76280M MAJOR MUNESH GUJAR, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

Read - IC-76280M MAJOR MUNESH GUJAR, 3RD BATTALION THE RAJPUT REGIMENT

At. S. No. 41

For – 427498Y HAVILDAR SREENATH MURMU, 47TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

Read - 427498Y HAVILDAR SREENATH MURMU, THE BIHAR REGIMENT/47TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

At. S. No. 51

For – 2611130M NAIK NATARAJAN N, 7TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT

Read - 2611130M LANCE NAIK NATARAJAN N, 7TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT

P. PRAVEEN SIDDHARTH

Officer on Special Duty

No. 87-Pres/2018.—The following amendments are made in the Hindi version of this Secretariat Notification No. 37-Pres/2017, dated 26th January, 2017 published in Part I Section 1 of the Gazette of India on the 25th March, 2017 relating to the award of 'Sena Medal' for the acts of exceptional devotion to duty:-

At. S. No. 3

For – IC-39690A MAJOR GENERAL HARISH THUKRAL, INFANTRY

Read - IC-39590A MAJOR GENERAL HARISH THUKRAL, INFANTRY

At. S. No. 22

For – IC-59491K COLONEL LAWINDER SINGH, THE BIHAR REGIMENT/ARTRAC HQ

Read - IC-51491K COLONEL LAWINDER SINGH, THE BIHAR REGIMENT

P. PRAVEEN SIDDHARTH

Officer on Special Duty

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

(ICR DIVISION)

New Delhi, the 26th July, 2018

No.F.9/1/2018-U.3 (A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as a Deemed to be University.

2. **And whereas**, an application was received on 17.01.2018 for grant of Deemed to be University status (under De-novo yet to be established category) to National Rail and Transportation Institute (NRTI), NAIR Campus, Lalbaug, Vadodara, Gujarat under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. **And whereas**, the application was forwarded to UGC for advice as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

4. **And whereas**, UGC constituted an Expert Committee to recommend whether the application of National Rail and Transportation Institute (NRTI), Vadodara, Gujarat may be considered under de-novo category. The Committee, after detailed deliberation and discussions with the representative of the Institution was of the opinion that the Courses proposed to be started are covered under the definition of 'De-novo' as envisaged in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 and are in the emerging areas of knowledge in true sense. The Committee has made the following recommendations:

"Letter of Intent (LoI) may be issued by the Ministry of HRD to the Institution for establishment of National Rail & Transportation Institute as an Institution Deemed to be University under de-novo category with the following conditions:

- i. A separate and exclusive society/trust/company to be created in the name of the proposed deemed to be university.
- ii. All the assets should legally vest in the name of the proposed deemed to be university.
- iii. MoA/Rules to be prepared in accordance with the UGC Regulations, 2016.
- iv. Land, Buildings, Library, Labs, Hostels, Residences and other Infrastructure to be created in accordance with the UGC Regulations, 2016.
- v. UG and minimum of five PG courses proposed in emerging area alongwith the detailed syllabi of the courses and research programmes to be conducted in the emerging areas of knowledge.
- vi. Faculty to be recruited for the proposed courses with the qualifications prescribed by the UGC.
- vii. Other authorities such as Vice-Chancellor, Registrar, etc. to be appointed.

The Committee further recommended that an Expert Committee of UGC may visit the National Academy of Indian Railways (NAIR), Vadodara (Gujarat) for on the spot visit of the infrastructure and other facilities available with the Institute and to recommend whether the facilities available are in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 for the courses proposed to be started. The Committee may also include one member from the present Committee."

5. **And whereas**, as required under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, another Expert Committee of UGC as well as that of All India Council for Technical Education (AICTE) visited the Institution during 18-19th April, 2018 for physical verification of infrastructure and other facilities available with the Institute. The Reports of both UGC & AICTE Expert Committees were considered by the Commission in its 531st meeting (Item No. 2.01) held on 11.05.2018 in which following resolution was passed:

"Considered and approved. National Rail and Transport Institute (NRTI), NAIR Campus, Lalbaug, Vadodara-390004, Gujarat for Deemed to be University status under de-novo category. Further, it was suggested that NRTI be advised to take appropriate steps for placement of the students."

6. **And whereas**, taking into consideration the report of UGC & AICTE Expert Committees and the advice of UGC, this Ministry had issued Letter of Intent (LoI) on 25.05.2018 to Ministry of Railways, Government of India for setting up National Rail and Transportation Institute (NRTI), Vadodara, Gujarat as an Institution Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 with the following conditions:

- i. A separate and exclusive society/trust/company shall be created in the name of the proposed deemed to be university.
- ii. All the assets shall be legally registered in the name of the proposed deemed to be university.
- iii. MoA/Rules to be prepared in accordance with the UGC Regulations, 2016.
- iv. UG and minimum of five PG courses proposed in emerging area along with the detailed syllabi of the courses and research programmes to be conducted in the emerging areas of knowledge.
- v. Faculty to be recruited for the proposed courses with the qualifications prescribed by the UGC.
- vi. Other authorities such as Vice-Chancellor, Registrar, etc. to be appointed.

7. **And further whereas**, Ministry of Railways, Government of India submitted its compliance report on 14th June, 2018 with regard to the conditions mentioned in LoI. The compliance report was forwarded to UGC for examination and sending its comments to this Ministry. In response, UGC sent its comments to this Ministry on 29th June, 2018.

8. **Now, therefore**, taking into consideration the advice of UGC and its further clarification on the compliance report of Ministry of Railways, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby declare *National Rail and Transportation Institute (NRTI), NAIR Campus, Lalbaug, Vadodara, Gujarat, as an Institution deemed to be University under De-novo category* for a provisional period of five years subject to conditions that the NRTU Foundation (a not-for-profit Company of Ministry of Railways, Government of India registered under Section 8 of Companies Act, 2013) will recruit the required number of faculty and appoint other authorities such as Vice-Chancellor, Registrar, etc. as per the norms of the UGC before starting academic activities in the NRTI. The status of Deemed to be University shall be confirmed after five years based on the review report of UGC Expert Committee and the recommendation of the Commission, as per the provisions of the prevailing Regulations.

9. The declaration as made in Para 8 above is further subject to fulfilment of the conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification;

ISHITA ROY

Joint Secretary